वर्ष 2005-2006 के लिए नई सेवा/सेवा के नवीन साधनों को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण
Statement showing Details of New Service/New Instrument of Service for 2005-2006

क्रम. सं.	विवरण	Sl. No.	Particulars	बजट अनुमान 2005-2006 में शामिल व्यवस्था (करोड़ रुपए) Provision included in BE 2005-2006 (Rs. in crore)	संक्षिप्त उद्देश्य	Brief objective
1	2	3	4	5	6	7
1.	**मांग सं. 1- कृषि एवं सहकारिता विभाग**	**1.**	**Demand No.1- Department of Agriculture & Cooperation**			
	शुष्क भूमि/वर्षासिंचित कृषि प्रणाली की सततता को बढ़ाना		Enhancing Sustainablity of Dryland/Rainfed Farming System	200 .00	यह योजना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल है। शुष्क भूमि कृषि में मुख्य बाधाएं आर्द्रता/ जल के संरक्षण की हैं, जो कृषि योग्य क्षेत्र/भूखंण्ड में कृषि प्रणाली को प्रभावित करती हैं। प्रस्तावित योजना के तहत वर्षा के जल का संचयन, जल सरक्षण, जल का प्रभावी उपयोग और विशेषतः जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में प्रयोग पर और जोर देने का प्रस्ताव किया गया है। वर्षासिंचित कृषि में वृद्धि करने और भूमि की उत्पादकता में सुधार करने के लिए खेती के उपकरणों, उपस्कर, मशीनों, औजारों और कृषि संबंधी निविष्टियों आदि के लिए कृषकों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।	The scheme is one of the Common Minimum Programmes of the UPA Govt. The major constraints in dryland agriculture is conservation of moisture/water which governs the cropping pattern over a farm holding/plot. Under the proposed scheme rainwater harvesting, water conservation, efficient use of water and especially as life saving irrigation is proposed to be given a thrust. To develop the rainfed farming and improve the land productivity it is proposed to provide support to farmers for on-farm work, equipments, machines, implements and agricultural inputs etc.
	एसएफसीआई/एनएससी की पुनर्संरचना		Restructuring of SFCI/NSC	38.00	एसएफसीआई की निवल सम्पत्ति पूरी तरह से कम हो गई है क्योंकि निगम ने दिनांक 31.3.04 की स्थिति के अनुसार 25.00 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी और 24.19 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी की तुलना में 91.93 करोड़ रुपए की हानियों का संचयन किया है। उसी प्रकार एनएससी की निवल सम्पत्ति में पर्याप्त रूप से कमी हुई है क्योंकि दिनांक 31.3.04 की स्थिति के अनुसार निगम ने 21.00 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी और 20.62 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी की तुलना में 15.61 करोड़ रुपए की हानियां का संचन किया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में गुणवत्ता वाले बीजों के आधार निविष्टियों में कार्य करने वाले दोनों निगमों की पुनर्संरचना पर विचार	The net worth of SFCI has been completely eroded as the corporation has accumulated losses of Rs.91.93 crores as on 31.3.04 as against the authorised capital of Rs.25.00 crores and paid up capital of Rs. 24.19 crores. Similarly the net worth of NSC has been substantially eroded as the corporation has accumulated losses of Rs.15.61 crores as on 31.3.04 as against the authorised capital of Rs.21.00 crores and paid up capital of Rs.20.62 crores. In view of this restructuring of both the corporations dealing in the basic input of quality seeds in agriculture sector is under

क्रम. सं.	विवरण	Sl. No.	Particulars	बजट अनुमान 2005-2006 में शामिल व्यवस्था (करोड़ रुपए) Provision included in BE 2005-2006 (Rs. in crore)	संक्षिप्त उद्देश्य	Brief objective
1	2	3	4	5	6	7
					किया जा रहा है। इसलिए वर्ष ब.अ. 2005-06 में इन निगमों के लिए 38.00 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान का प्रावधान है।	consideration. Hence, a provision of Rs.38.00 crores is required for grants-in-aid to these corporations in BE 2005-06.
भारतीय कृषि में प्रति स्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु क्षमता निर्माण		Capacity Building to Enhance Competitiveness of Indian Agriculture	1.00	भारत में कृषि को एक लाभकारी तथा व्यवहार्य व्यवसाय के रूप में बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रणाली में ऐसी क्षमताओं का निर्माण, जो वैश्विकीकरण की शक्तियों का मुकाबला करने और जहाँ कहीं संभव हो प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो/भारतीय कृषि मे प्रति स्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु क्षमता निर्माण नामक नई योजना का उद्देश्य कतिपय सीमित लघु स्तर के क्षमता सृजन मामलों का समाधान करना है। यह योजना राज्य सरकारों अथवा अन्य निजी, अर्ध-सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा एक लागत भागीदारी आधार पर शुरू की जाएगी। योजना के तैयारी में, अतिरिक्त मानव शक्ति को किराये पर लेने सहित स्थापना संबधी व्ययों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मुख्य कार्यकलाप हैं:- (i) भारतीय कृषि की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के विभिन्न पक्षों पर अनुसंधान अध्ययन/परामर्श। (ii) प्रमुखतया राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा देश के कृषकों/ कृषि वैज्ञानिकों/प्रशासकों के बीच कृषि पर डब्ल्यूटीओ करार और संबंधित करारों के संबंध में जागरूकता, सृजन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता देना। (iii) कृषकों को सहायता।	In order to retain agriculture as a remunerative and viable occupation in India, it is necessary to build capacities in the system, such that it is able to withstand the forces of globalization and compete wherever possible. The new scheme call Capacity Building to Enhance the Competitiveness of Indian agriculture aims to address some limited micro-level capacity creation issues. The scheme shall be operated on a cost sharing basis with State Governments or other private, semi government, non-government organizations. In the formulation of the scheme, no provision has been made for establishment related expenses including hiring of additional manpower. The main proposed activities under the scheme are :- (i) Research studies/ consultancy on various aspects of the international competitiveness of Indian agriculture. ii) Support for awareness, creation and training programmes relating to the WTO Agreement on agriculture and related agreements among farmers/ agricultural scientists/ administrators in the country, preferably by State Agricultural Universities. iii) Support to farmers.
लघू कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी)		Small Farmers Agri Business Consortium (SFAC)	30.00	देश में कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी), एक	With a view to promote agri-business in the country, the Small Farmers Agri-Business

क्रम. सं.	विवरण	Sl. No.	Particulars	बजट अनुमान 2005-2006 में शामिल व्यवस्था (करोड़ रुपए) Provision included in BE 2005-2006 (Rs. in crore)	संक्षिप्त उद्देश्य	Brief objective
1	2	3	4	5	6	7
					स्वायत्त निकाय, आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि-व्यवसाय परियोजनाओं की तैयारी में जुड़े उत्पादक समूहों/ संगठनों को सहायता देने हेतु कृषि-व्यवसाय परियोजनाओं और परियोजनाओं और परियोजना विकास सुविधा को उद्यम पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए एक नयी योजना को तैयार करने की प्रक्रिया में है। इस योजना में भाग लेने वाले बैंकों के जरिए संचालित की जाने वाली उद्यम पूंजी का संवितरण और विनिवेश के लिए एकल विंडों प्राचालन की व्यवस्था है। इससे एसएफएसी और उधार देने वाले बैंकों के बीच निकट भागीदारी संभव होगी। वर्ष 2004-05 के वार्षिक बजट में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस प्रयोजन हेतु एसएफएसी को पूंजी प्रदान करने की घोषणा की है।	Consortium (SFAC), an autonomous body is in the process of formulating a new scheme to provide Venture Capital Assistance to Agribusiness projects and a Project Development Facility to assist producer groups/ organisations in formulation of economically viable agri-business projects. The scheme envisages a single window operation for the disbursement and dis-investment of venture capital to be operated through the participating banks. This would involve a close partnership between the SFAC and the lending Banks. The Union Finance Minister has in the annual budget of 2004-05 announced to provide capital to SFAC for the purpose.
2.	**मांग सं. 5- परमाणु ऊर्जा**	**2.**	**Demand No.5- Atomic Energy**			
	एचडब्लूपी (बी) में सीपीपी की संस्थापना		Setting up of CPP at HWP (B)	0.05	------	------
	मानूगुरू में ऐश पौंड, एचडब्ल्यूपी का आशोधन और विस्तार (दूसरा चरण)		Modification and Extension of the Ash Pond at HWP, Manuguru (2nd stage)	0.05	------	------
	बड़ौदा सुदृढ़ीकरण		Baroda Augmentation	0.10	------	------
	हिलियम का उत्पादन		Production of Helium	0.10	------	------
	एचडब्लूपी में विलायक निष्कर्षण परीक्षण सुविधा		Solvent extraction test facility at HWPs	0.10	------	------
	एफआरएफसीएफ की परियोजनापूर्व गतिविधियां		Pre-project activities of FRFCF	1.00	------	------
	बुनियादी और अनु-प्रयुक्त अनुसंधान हेतु सीआईआरयूएस रिएक्टर उपयोग कार्यक्रम		CIRUS Reactor Utilisation Programme for Basic and Applied Research	1.00	------	------

क्रम. सं.	विवरण	Sl. No.	Particulars	बजट अनुमान 2005-2006 में शामिल व्यवस्था (करोड़ रुपए) Provision included in BE 2005-2006 (Rs. in crore)	संक्षिप्त उद्देश्य	Brief objective
1	2	3	4	5	6	7
	लेजर उत्प्रेरित आघात अध्ययन और लेजर आधारित न्यूट्रोन स्रोत		Laser induced shock studies and Laser based neutron sources	6.00	------	------
	लंबे कठोर एक्स-रे दपर्णों के लिए कोटिंग सुविधा का विकास		Developent of Coating facility for long hard X-ray Mirrors	1.50	------	------
	बीएआरसी अंतर्समूह कार्यक्रम - माइक्रो/नैनो प्रौद्योगिकी कार्यक्रम और संबद्ध क्षेत्र		BARC Inter Group Programme-Micro/NanoTechnology Programme and related areas	7.00	------	------
	बीएआरसी हेतु भौतिक सुरक्षा प्रणाली-तारापुर एवं कलपक्कम		Physical Protection System for BARC, Tarapur and Kalpakkam	8.40	------	------
	विजन प्रक्रिया		Vision Exercise	3.50	------	------
	एमईएमएस और एनईएमएस में अनुप्रयोग के लिए नानोकिरणों के विकास का अध्ययन		Study for Development of Nanobeams for Applications in MEMS and NEMS	0.20	------	------
	वीईसीसी का विस्तार		Expansion of VECC	10.00	------	------
3.	**मांग सं.12 - वाणिज्य विभाग** विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता	**3.**	**Demand No.12-Department of Commerce** Foreign Trade & Export Promotion-National Export Insurance Account	200.00	परियोजना तथा अन्य उच्च मूल्य निर्यातों के लिए ऋण जोखिम कवच की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए।	To ensure the availability of credit risk cover for projects and other high value exports.
4.	**मांग सं. 13- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग** पूर्वी एवं उत्तरपूर्वी क्षेत्र आधारभूत ढांचा विकास	**4.**	**Demand No.13-Department of Industrial Policy & Promotion** Infrastructure Development in Eastern and North Eastern Region	1.00	पूर्वी क्षेत्र एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिकीकरण में तेजी लाने के लिए उचित मध्यस्थताओं के माध्यम से आधारभूत ढांचे के एकीकृत विकास के उद्देश्य इस स्कीम को एक पंचवर्षीय अवधि के दौरान क्रियान्वित किया जाना है और इसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सभी आठ राज्यों, बिहार, प.बंगाल, झारखंण्ड., और उड़ीसा को कवर किया जाएगा।	The objective of the integrated development of infrastructure through appropriate interventions is to speed up the industrialization in the Eastern Region & North Eastern Region. The scheme is to be implemented during a five year period and will cover all

क्रम. सं.	विवरण	Sl. No.	Particulars	बजट अनुमान 2005-2006 में शामिल व्यवस्था (करोड़ रुपए) Provision included in BE 2005-2006 (Rs. in crore)	संक्षिप्त उद्देश्य	Brief objective
1	2	3	4	5	6	7
						the eight States in North Eastern Region, Bihar, West Bengal, Jharkhand and Orissa.
	पूंजी निवेश सब्सिडी		Capital Investment Subsidy	0.01	विकास केन्द्रों में स्थित उद्योगों और नए उद्योग एककों की और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के अन्य अभिज्ञात क्षेत्रों में भुगतान-योग्य 30 लाख की सीलिंग के अधीन संयत्र एवं मशीनरी में निवेश के 15% की दर पर सब्सिडी प्रदान करना।	For providing subsidy @ 15% of the investment in the plant & machinery subject to ceiling of 30 lakh payable to industries located in the Growth Centres and to new industrial units and in other identified areas of North Eastern Region and Sikkim.
	केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी		Central Interest Subsidy	0.01	नए औद्योगिकी एककों तथा/अथवा उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम में उत्पादन का काम करने के बाद अन्य अभिज्ञात क्षेत्रों में उनके विस्तार पर 10 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए कार्यशील पूंजी पर 3% की दर पर सब्सिडी प्रदान करेगा।	For providing subsidy @ 3% on working capital payable for a maximum period of 10 years to the new industrial units and/or their expansion in other identified areas in the North Eastern Region and Sikkim after the unit goes into production.
	उत्तर-पूर्व के लिए समग्र स्कीम		Comprehensive Insurance Scheme for North East	0.01	उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम में स्थापित नए औद्योगिक एककों और अग्नि नीति ग में शामिल (अखिल भारतीय अग्नि टैरिफ के अनुसार) दस वर्षों की अवधि हेतु 100% की बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए।	For providing reimbursement of 100% insurance premium for a period of ten years to the new industrial units set up in the North Eastern Region and Sikkim and included in the fire policy C (as per All India Fire Tariff).
	अन्य राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम पहल		Other NCMP Initiative	19.00	पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक आधारभूत ढांचा विकास और पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यवहार्यता अध्ययन आदि के संचालन में अंतर्ग्रस्त किसी भी व्यय के लिए।	For the development of industrial infrastructure in the Eastern Sector and also for any expenditure involved in conducting the feasibility study, etc. for the Eastern Region.
5.	**मांग संख्या 30 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**	**5.**	**Demand No.30- Ministry of Environment & Forests**			
	उत्तर पूर्व में बांस का ग्रेगेरियस पुष्पण		Gregarious flowering of bamboo in North East.	35.00	------	------

क्रम. सं. विवरण	Sl. No. Particulars	बजट अनुमान 2005-2006 में शामिल व्यवस्था (करोड़ रुपए) Provision included in BE 2005-2006 (Rs. in crore)	संक्षिप्त उद्देश्य	Brief objective
1 2	3 4	5	6	7
6. मांग संख्या 34 वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	**6. Demand No.34- Payment to Financial Institutions**			
भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश	Investment in the Life Insurance Corporation of India Ltd.	280.00	एलआईसी की सामान्य प्रारक्षित निधियों को बढ़ाना जो कि अंश धारियों की निधियों के भाग का निर्माण करती हैं।	To augment the general reserve of LIC, which forms part of the shareholders funds.
7. मांग संख्या 39 व्यय विभाग	**7. Demand No.39- Department of Expenditure**			
अंशदान	Contribution	0.01	एशिया के सरकारी लेखे संगठन के एशोसिएसन को अंशदान	Contribution to Association of Government Accounts Organization of Asia.
8. मांग संख्या 42 राजस्व विभाग	**8. Demand No.42- Department of Revenue**			
राज्यों को क्षतिपूर्ति	Compensation to States	5000.00	मूल्यवर्धन कर को लागू करने के कारण राज्यों को हुए राजस्व घाटे के संबंध में क्षतिपूर्ति	Compensation to States for revenue loss due to introduction of Value Added Tax (VAT).
9. मांग संख्या 58 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा	**9. Demand No.58- Department of Secondary and Higher Education**			
इंजीनियसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लायब्रेरी	Indian National Digital Library in Engineering Science and Technology (INDEST) Consortium	22.00	आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों को ई-जर्नल और इलैक्ट्रानिक डाटाबेस के संकाय आधारित अभिदानों के लिए सहायता देना।	To assist institutions like IITs, NITs, IIMs, etc. for consortia based subscriptions of E-Journals and electronic data base.
तमिल भाषा का विकास	Development of Tamil Language	0.90	सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डियन लैंग्वेजिस, मैंसूर के जरिए प्रचालित की जाने वाली इस योजनामें विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए तमलि भाषा के विकास की परिकल्पना की गई है।	To be operated through the Central Institute of Indian Languages, Mysore, the scheme envisages development of Tamil Language through various programmes.
सीआईटी, कोकराझार	CIT, Kokrajhar	0.01	------	------
आईआईएम(उत्तर पूर्व)	IIM (North East)	0.01	------	------
10. मांग संख्या 61 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	**10. Demand No.61- Ministry of Labour & Employment**			
उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम में नए औद्योगिक संस्थानों की स्थापना	Eastablishment of New Industrial Training Institutes in North Eastern States and Sikkim	22.69	उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम में नए औद्योगिक संस्थानों की स्थापना में सहायता।	To assist establishment of ITIs in NE Region and Sikkim.

क्रम. सं. विवरण	Sl. No. Particulars	बजट अनुमान 2005-2006 में शामिल व्यवस्था (करोड़ रुपए) Provision included in BE 2005-2006 (Rs. in crore)	संक्षिप्त उद्देश्य	Brief objective
1 2	3	4	5	6	7
11. मांग संख्या 63 विधि एवं न्याय	**11. Demand No.63- Law & Justice**			
न्याय प्रशासन	Administration of Justice	192.00	यह प्रावधान जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए हैं।	The provision is for computerization of District and Subordinate Courts.
12. मांग संख्या 70 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	**12. Demand No.70- Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions**			
सूचना की उपलब्धता के लिए क्षमता निर्माण हेतु यूएनडीपी परियोजना	UNDP Project-Capacity Building for access to information	2.00	इस परियोजना का उद्देश्य चुनिंदा जिलों में सरकारी अधिकारियों द्वारा सूचना प्रदान करने तथा नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने संबंधी कार्यों में दक्षता और क्षमता में वृद्धि करने संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। इन कार्यों में, सूचना के आदान-प्रदान के लिए सूचना समाशोधन गृहों की स्थापना करना, नागरिकों में जागृति एवं क्षमता का विकास करना तथा सूचना के अधिकार के सुगम प्रचालन के लिए संस्थागत/वैधानिक ढांचा तैयार करना शामिल हैं। इस परियोजना का वित्तपोषण यूएनडीपी द्वारा किया जाएगा तथा परियोजना को अवधि तीन वर्ष की होगी।	The project aims to set up facilities in selected districts to enhance the skill and capacity of Govt. officials as information providers and citizens as information seekers. The activities include establishment of information Clearing Houses for sharing of information, developing of awareness and capacity of citizens to seek information and institutional/legal framework for smooth operation of Right to Information. The project will be funded by grant assistance from the UNDP and the project period will be for three years.
निर्धनता उन्मूलन हेतु क्षमता निर्माण संबंधी डीएफआईडी परियोजना (प्रशिक्षण घटक)	DFID project on capacity building for poverty reduction (Training Component)	1.00	इस परियोजना का उद्देश्य संगठनात्मक विकास तथा मानव संसाधन विकास संबंधी उपायों के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन के लिए क्षमता निर्माण करना है। इस परियोजना को डीएफआईडी से मिलने वाली अनुदान सहायता द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा तथा परियोजना की अवधि तीन वर्ष होगी।	The project is intended for capacity building for poverty reduction through organizational development and human resource development initiatives. The project is financed through grant assistance from DFID and the project period will be for three years.
परियोजना मूल्यांकन हेतु क्षमता निर्माण	Capacity building for project appraisal	1.50	इस परियोजना के अंतर्गत देश के अंदर अवसंरचना क्षेत्र के लिए प्रबंधन क्षमता का निर्माण करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना द्वारा अवसंरचना विकास संबंधी क्षमता निर्माण हेतु रूप रेखा, विषय-वस्तु तथा कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने	The project will provide assistance through training programmes to build managerial capacity in the country for the infrastructure sector. The project will provide direct support for

क्रम. सं. विवरण	Sl. No. Particulars	बजट अनुमान 2005-2006 में शामिल व्यवस्था (करोड़ रुपए) Provision included in BE 2005-2006 (Rs. in crore)	संक्षिप्त उद्देश्य	Brief objective
1 2	3 4	5	6	7
			के लिए सीधी सहायता प्रदान की जाएगी। इस स्कीम का वित्तपोषण प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।	improving the design, content and methodologies for infrastructure development capacity building. The scheme will be funded through Annual Plan Mechanism every year.
सिविल सेवा कालेज की स्थापना	Setting up of Civil Service College	0.01	इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवाकालीन गहन तथा अनिवार्य प्रशिक्षण देने के लिए एक सिविल सेवा कालेज की स्थापना करना है जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों को दक्षता तथा कुशलता के साथ निपटा सकें।	The objective of the project is to equip the civil servants in India to discharge their responsibility professionally and efficiently by establishing a Civil Service College to provide intensive and mandatory mid-career training to civil servants.
प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना	Setting up of Administrative Reforms Commission	8.00	प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना न्यूनतम साझा कार्यक्रम की एक मद है तथा इसका उद्देश्य सरकारी प्रशासनिक प्रणाली के नवीकरण के लिए एक विस्तृत रूप रेखा तैयार करना है।	Setting up of Administrative Reforms Commission is a CMP item and is intended to prepare a detailed blueprint for revamping the public administration system.
13. मांग संख्या 72 योजना मंत्रालय	**13. Demand No.72- Ministry of Planning**			
प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद	Economic Advisory Council to the Prime Minister	1.71	प्रधानमंत्री ने आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन को अनुमोदित कर दिया है जो प्रधानमंत्री द्वारा उसे सौंपें गए किसी भी मुद्दे, जो आर्थिक अथवा कोई अन्य मुद्दा हो सकता है, का विश्लेषण करेगी तथा उस पर सलाह देने के अलावा वृहत्-आर्थिक महत्व के मुद्दों का समाधान करेगी और उसके संबंध में प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेगी।	The Prime Minister has approved the constitution of the Economic Advisory Council to the PM for analysing any issue, economic or otherwise referred to it by the PM, besides addressing issues of macro-economic importance and presenting views thereon to the PM.
14. मांग संख्या 82 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	**14. Demand No.82- Department of Science & Technology**			
औषधि एवं मेषज अनुसंधान	Drugs & Pharmaceuticals Research	70.00	औषधि एवं मेषज अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करना।	To provide assistance for Drug and Pharmaceuticals Research.

क्रम. सं.	विवरण	Sl. No.	Particulars	बजट अनुमान 2005-2006 में शामिल व्यवस्था (करोड़ रुपए) Provision included in BE 2005-2006 (Rs. in crore)	संक्षिप्त उद्देश्य	Brief objective
1	2	3	4	5	6	7
	औषधि एवं भेषज अनुसंधान		Drugs & Pharmaceuticals Research	80.00	औषधि एवं भेषज अनुसंधान के लिए ऋण सहायता प्रदान करना।	To provide loan assistance for Drug and Pharmaceuticals Research.
	नैनो-विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी संबंधी मिशन		National Mission on Nano-Science and Nano-Technology	200.00	------	------
15.	**मांग संख्या 105 युवा मामले और खेल मंत्रालय**	**15.**	**Demand No.105-Ministry of Youth Affairs & Sports**			
	राष्ट्रमण्डल खेल 2010		Commonwealth Games 2010.	45.50	------	------